*कोविड के बाद: एक मजबूत, समावेशी और सतत अर्थव्यवस्था की ओर**

शक्तिकांत दास

मैं अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन है और यह उपयुक्त है कि एआईएमए इसका आयोजन कर रहा है। सामान्य समय में और इससे भी अधिक गंभीर तनाव के समय में, यह प्रबंधन की गुणवत्ता और क्षमता है जो महत्वपूर्ण अंतर बनाती है और व्यवसायों को न केवल जीवित रहने बल्कि मजबूत बनने में सक्षम बनाती है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि एआईएमए उद्योग, सरकार, शिक्षाविदों और छात्रों के साथ सहयोग करके प्रबंधन के पेशे को आगे बढ़ा रहा है।

इस सम्मेलन का विषय, "रिकवरी के बाद: खेल के नए नियम" जो बिलकुल सही समय पर है। अठारह महीने की लंबी लड़ाई के बाद, ऐसे संकेत हैं - और मैं संकेत दोहराता हूं - कि दुनिया कोरोनावायरस की छाया से उभर रही है। जैसा कि हम वर्तमान संकट से बाहर निकलते हैं और आगे देखते हैं, यह थोड़ा पीछे हटने और एक ऐसी अर्थव्यवस्था की योजना बनाने का सही समय है जो अधिक मजबूत, अधिक समावेशी और टिकाऊ हो। मैं आज अपनी टिप्पणी में ऐसी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा पर प्रकाश डालने का प्रस्ताव करता हूं।

कोविड-19 के बाद के जीवन की कल्पना

कोविड-19 हमारे युग की एक ऐतिहासिक घटना है। इसने जीवन और आजीविका की व्यापक तबाही मचाई है और यह अभी भी कई तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को परेशान कर रहा है। इतिहास में कोविड-19 के समान आघात की बहुत कम समानताएं हैं, जिसने नीति निर्माताओं को संकट से उबरने के लिए कोई खाका नहीं छोड़ा। संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली और मानव प्रयास दोनों को एक सीमा तक बढ़ाया गया था। अर्थव्यवस्था और समाज के कार्य करने के तरीके पर महामारी द्वारा एक अमिट छाप छोड़ने की संभावना है। जब हम संकट से बाहर निकलते हैं तो एक नई सुबह, एक नया सामान्य होने की संभावना है।

महामारी ने कई संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रेरित किया है जिसने हमारे काम करने, रहने और व्यवसायों को व्यवस्थित करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। घर से काम करने पर ज़्यादा झुकाव के साथ, यात्रा के समय की बचत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री को बढ़ावा देने और स्वचालन की गति को तेज करके, प्रौद्योगिकी ने उत्पादकता को बढ़ावा देने की क्षमता हासिल की है। नतीजतन, खपत स्वरूप बदल रहा है और कंपनियां विश्व स्तर पर और साथ ही स्थानीय स्तर पर अपनी आपूर्ति श्रृंखला को फिर से निर्धारित कर रही हैं। इन परिवर्तनों का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला महत्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजर रही है; कंपनियों और विभिन्न प्राधिकरणों को इन अवसरों को पूंजीकृत करने के लिए पर्याप्त कुशल होना चाहिए। स्वचालन और रोबोटिक्स से कम-कुशल श्रमिकों और संपर्क-गहन क्षेत्रों में काम करने वालों को खतरा होगा। ऑनलाइन की तरफ झुकाव ने यात्रा, होटल, रेस्तरां और मनोरंजन जैसे रोजगार-केंद्रित क्षेत्रों के लिए नए अवसर और चुनौतियां भी पैदा की हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन महामारी के बाद भी रहने वाले हैं। सहभागी वृद्धि प्रक्रिया के लिए कार्यनीति तैयार करते समय इन संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

दूसरे स्तर पर, महामारी ने गरीबों और कमजोर लोगों को अधिक प्रभावित किया है, खासकर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। दैनिक वेतन भोगी, सेवा और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उनके रोजगार और आय के अवसरों को कम कर दिया गया। इन क्षेत्रों में महामारी से हुई स्थायी क्षति समावेशी वृद्धि के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मध्यम से दीर्घावधि में, सतत विकास और व्यापक आर्थिक निष्पादन के लिए दक्षता और इक्विटी दोनों ही बहुत मायने रखेंगे।

प्रौद्योगिकी को अपनाना जो पहले मुख्य क्षेत्रों तक सीमित था, अब कई अन्य क्षेत्रों तक पहुंच गया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खुदरा व्यापार और कार्यालय। महामारी ने भी व्यवधान

* गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्य भाषण - बुधवार, 22 सितंबर, 2021 - अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) के 48वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में दिया गया।

पैदा किया है और सभी क्षेत्रों में श्रम और पूंजी के पुनर्वितरण को प्रेरित किया है। जो फर्में प्रौद्योगिकी अपनाने में तेज थीं और ऑफ-साइट से काम करने में लचीली थीं, वे अधिक पूंजी और श्रम को आकर्षित कर रही हैं। दूसरी ओर, जो फर्में चुनौती और प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं थीं, उन्हें अधिक सक्रिय लोगों के लिए जगह छोड़नी होगी। 'रचनात्मक विनाश' की इन ताकतों से अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में अधिक प्रतिस्पर्धा, गतिशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करके उत्पादकता को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

भारतीय परिदृश्य

अब मैं भारतीय परिदृश्य की ओर मुड़ता हूं। महामारी के बाद की दुनिया में, भारत की संभावनाओं को कई गतिशील क्षेत्रों द्वारा रेखांकित किया गया है। मैं उनमें से कुछ पर संक्षेप में बात करना चाहता हूं।

पहला, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाएं और सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाएं (आईटीईएस) जो उद्यमशीलता की क्षमताओं और नवीन समाधानों द्वारा समर्थित हैं, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख ताकत के रूप में उभरी हैं। भारत में यूनिकॉर्न का बढ़ता हुआ संघ प्रौद्योगिकी-आधारित वृद्धि के लिए इसकी क्षमता को दर्शाता है। देश ने पिछले एक साल में कई यूनिकॉर्न जोड़े हैं और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम बन गया है। कम प्रवेश वाले भारतीय बाजार और बड़े आईटी प्रतिभा पूल नए युग की फर्मों के लिए अभूतपूर्व वृद्धि का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा, कोविड महामारी ने फिनटेक, एडटेक और हेल्थटेक जैसी प्रौद्योगिकी-संचालित कंपनियों को एक नया प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिन्हें आने वाले वर्षों में निधिकरण गतिविधि में वृद्धि देखने की संभावना है।

दूसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्राहक समस्या निवारण, डेटा विश्लेषण, कार्यस्थल परिवर्तन, आपूर्ति शृंखला स्वचालन, 5G आधुनिकीकरण और साइबर सुरक्षा क्षमताओं जैसे क्षेत्रों में मजबूत मांग के साथ भारत की डिजिटल गति जारी रहने की उम्मीद है। भारत की इन क्षेत्रों में उभरती प्रवृत्तियों से लाभ उठाने की बढ़त स्वाभाविक है। अर्थव्यवस्था के पूर्ण रेशायीकरण की दिशा में अभियान को डेटा संचयन और प्रसंस्करण के लिए देश भर में डेटा केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ चलना होगा। पूरे देश में सार्वभौमिक, सस्ती और तेज ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना उत्पादकता और रोज़गार के अवसरों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा, डिजिटलीकरण और स्वचालन पर ज़ोर व्यवसाय करने में आसानी पर अधिप्लावन प्रभाव डाल सकता है। चिकित्सा प्रगति और प्रक्रिया में तेजी सार्वजनिक स्वास्थ्य नवाचारों और वितरण में पुनर्जागरण को बढ़ावा दे सकती है। ई-कॉमर्स भारत के लिए एक और आशाजनक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इसे बढ़ते बाजार, इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ और उपभोक्ता वरीयताओं में कोविड-प्रेरित बदलाव से लाभ हुआ है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्किल इंडिया और इनोवेशन फंड जैसे सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों ने डिजिटल क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है।

तीसरा, महामारी ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि भारत विनिर्माण के क्षेत्र में क्या हासिल कर सकता है। इतिहास में पहली बार फार्मास्युटिकल क्षेत्र में, टीकों का विकास और प्रशासन एक वर्ष के भीतर किया गया था और भारत वैक्सीन निर्माण में एक अग्रदूत और वैश्विक नेता बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना में निवेशकों ने भरोसा दिखाया है। इस पहल के बाद, भारत अब लगभग सभी प्रमुख वैश्विक मोबाइल फोन निर्माताओं का घर है और हाल की अवधि के दौरान, भारत एक आयातक से मोबाइल फोन के निर्यातक में बदल गया है। इस प्रवृत्ति की अन्य क्षेत्रों में भी फैलने की संभावना है। वैश्विक कंपनियों की उपस्थिति से वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने और एक प्रतिरोधक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी। अधिक जीवीसी भागीदारी भारत के बड़े और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आपूर्तिकर्ता आधार की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाएगी।

चौथा, हरित प्रौद्योगिकी की ओर वैश्विक ज़ोर, हालांकि विघटनकारी है लेकिन कई क्षेत्रों में नए अवसर पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र विद्युत वाहनों की ओर बढ़ रहा है। अधिक नवाचार के साथ, इलेक्ट्रिक वाहन धीरे-धीरे लागत और प्रदर्शन में आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) में परिवर्तित हो

रहे हैं। सबसे बड़ी विद्युत वाहन कार निर्माता पारंपरिक कार निर्माता कंपनियों से नहीं है। दोपहिया क्षेत्र में भी इसी तरह का रचनात्मक व्यवधान दिखाई दे रहा है। सहायक नीतियों के साथ, हरित प्रौद्योगिकियां आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

पांचवां, भारत का ऊर्जा क्षेत्र भी महत्वपूर्ण मंथन और तकनीकी परिवर्तन देख रहा है। जैसे-जैसे भारत तेजी से बढ़ रहा है, निकट भविष्य में इसकी ऊर्जा मांग बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में, महत्वपूर्ण आयात निर्भरता के साथ, ऊर्जा की मांग का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन से पूरा किया जाता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों के हिस्से के रूप में, भारत का लक्ष्य 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत (450जीडबल्यू) तक बढ़ाना है।[1] कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम शुरू किया था, जो ईंधन के आयात पर बचत के अलावा हवा को स्वच्छ करने में मदद करेगा। तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल सम्मिश्रण का प्रतिशत 2013-14 में 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 5.0 प्रतिशत हो गया है और 2025 तक 20 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से 2021-22 में बढ़कर 8.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है।[2] अक्षय ऊर्जा की दिशा में अभियान ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता दोनों के लिए सही दिशा में एक कदम है, जो हमारे दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

छठवां, महामारी के बाद की अवधि में, तेजी से रिकवरी के लिए वैश्विक व्यापार महत्वपूर्ण रहेगा। अनुकूल नीतिगत माहौल और सहायक बाहरी मांग को दर्शाते हुए, भारत का निर्यात 2021-22 की पहली छमाही के दौरान व्यापक-आधार दोहरे-अंकों की वृद्धि के साथ फिर से शुरू हुआ है। नए गंतव्यों के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) प्रमाणित उत्पादों सहित कृषि वस्तुओं का भारत का निर्यात, समग्र निर्यात के लिए अनुकूल संभावनाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात - जो भारत के कुल निर्यात का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है - उत्पाद श्रेणियों और नए बाजारों में मजबूत वृद्धि का अनुभव किया। निर्यात क्षमता को और मजबूत करने के लिए, 2030 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च-तकनीक के इंजीनियरिंग निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।[3]

अब तक जिन सभी क्षेत्रों का मैंने उल्लेख किया है, उन सभी क्षेत्रों में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, हमें परिवहन और संचार के अलावा विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, कम कार्बन और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कृषि और बागवानी क्षेत्र में मूल्यवर्धन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए गोदाम और आपूर्ति-श्रृंखला का इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण होगा। इससे अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन व्यापार में भारी उछाल के चलते टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ गई है। इसके अलावा, अमूर्त पूंजी में निवेश जैसे अनुसंधान और विकास और मानव संसाधन के कौशल उन्नयन का उत्पादकता पर मजबूत और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि अमूर्त पूंजी में निवेश का श्रम उत्पादकता पर प्रभाव मूर्त पूंजी में निवेश से अधिक है।[4]

सातवां, एक गतिशील और प्रतिरोधक वित्तीय प्रणाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था के मूल में है। अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की वित्तीय प्रणाली तेजी से बदली है। जबकि अर्थव्यवस्था में बैंक क्रेडिट के प्राथमिक चैनल रहे हैं, हाल के रुझान गैर-बैंक निधिकरण चैनलों की बढ़ती भूमिका का सुझाव देते हैं। एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड जैसे गैर-बैंक वित्तीय

[1] पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति "जलवायु परिवर्तन पर भारत के सीईओ फोरम में जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे" दिनांक 4 नवंबर 2020।

[2] भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोडमैप 2020-25, भारत सरकार, जून 2021।

[3] पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति "ईईपीसी ने इंजीनियरिंग निर्यात पुरस्कारों के 50 वें वर्ष का जश्न मनाया" दिनांक 10 दिसंबर 2019।

[4] आईएमएफ (2021), "कोविड -19 के बाद उत्पादकता में वृद्धि", जी -20 पृष्ठभूमि टिप्पणी, जून।

मध्यस्थों की आस्तियां बढ़ रही है; कॉरपोरेट बॉन्ड जैसे बाज़ार लिखत के जरिए निधिकरण भी बढ़ रहा है। यह एक लगातार परिपक्व होने वाली वित्तीय प्रणाली का संकेत है - एक बैंक-प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणाली से एक मिश्रित प्रणाली की ओर बढ़ना। जोखिमों को पहचानने, मापने और कम करने के लिए वित्तीय संस्थानों के आंतरिक रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए पर्याप्त प्रगति की गई है। यह एक सतत प्रक्रिया है और सभी हितधारकों के प्रयासों को जारी रखना होगा।

अधिक समावेशी और स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर

इतिहास से पता चलता है कि वित्तीय और बैंकिंग संकटों के विपरीत, महामारी का प्रभाव, कमजोर वर्गों को अधिक प्रभावित करके बहुत अधिक विषम हो सकता है। कोविड-19 महामारी कोई अपवाद नहीं है। देशों के भीतर, बड़ी संख्या में अनौपचारिक, कम-कुशल और कम वेतन वाले श्रमिकों को रोजगार देने वाले संपर्क-गहन सेवा क्षेत्रों को अधिक प्रभावित किया गया है। कई उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, स्वास्थ्य देखभाल की कमी ने गरीबों के परिवार के बजट को असमान रूप से प्रभावित किया है। यहां तक कि शिक्षा जो महामारी के दौरान ऑनलाइन प्रदान की गई थी, आवश्यक कौशल और संसाधनों की कमी के कारण निम्न-आय हाउसहोल्ड को बाहर कर दिया। कुल मिलाकर, सभी देशों में इस बात के प्रमाण हैं कि महामारी ने समावेशिता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

वैश्विक रिकवरी भी देशों और क्षेत्रों में असमान रही है। टीकाकरण की उच्च गति और बड़े नीतिगत समर्थन के बल पर उन्नत अर्थव्यवस्थाएं तेजी से सामान्य हुई हैं। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं टीके तक कम पहुंच और नीतिगत समर्थन पर बाध्यकारी बाधाओं के कारण पिछड़ रही हैं। यदि बहुपक्षवाद सभी देशों में वैक्सीन की समान पहुंच सुनिश्चित करने में विफल रहता है तो उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। अगर हम गरीबों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा को सुरक्षित कर सकते हैं, तो हम समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं। इस मोर्चे पर तेजी से प्रगति के लिए वैश्विक सहयोग महत्वपूर्ण है।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि महामारी के बाद की दुनिया में समावेशी विकास के लिए सभी हितधारकों के सहयोग और भागीदारी की आवश्यकता होगी। भारत में, विभिन्न हितधारकों का सहयोगात्मक प्रयास टीकाकरण की गति को तेज करने के एक कठिन कार्य को पूरा करने में मदद कर रहा है। निजी क्षेत्र टीकों का विकास और निर्माण कर रहा है; केंद्र सरकार केंद्रीय रूप से इसकी खरीद और आपूर्ति कर रही है; और राज्य सरकारें इसे देश के कोने-कोने में पहुंचा रही हैं और प्रशासित कर रही हैं। भारत अब आबादी के सभी वर्गों में हर दिन वैक्सीन की लगभग एक करोड़ खुराक का रिकॉर्ड बना रहा है।

महामारी के बाद की दुनिया में समावेशिता के लिए एक बड़ी चुनौती महामारी द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन से लेकर स्वचालन तक आएगी। अधिक स्वचालन से समग्र उत्पादकता में वृद्धि होगी, लेकिन इससे श्रम बाजार में मंदी भी आ सकती है। ऐसा परिदृश्य हमारे कार्यबल के महत्वपूर्ण कौशल/प्रशिक्षण की मांग करता है। हमें "डिजिटल विभाजन" के उभरने से बचने की जरूरत है क्योंकि महामारी के बाद डिजिटलीकरण की गति तेज हो गई है। इसके अलावा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में प्रशिक्षित पेशेवर मानव संसाधनों की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। प्रमुख प्रौद्योगिकी-आधारित फर्मों ने इन क्षेत्रों में कौशल के साथ कई नए पेशेवरों को नियुक्त करने का इरादा व्यक्त किया है। अल्पावधि में, ऐसे कार्यबल की आपूर्ति को पारंपरिक शैक्षिक प्रणाली द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है, और इस प्रकार बदलते औद्योगिक परिदृश्य के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रमों के डिजाइन और कार्यान्वयन में कॉर्पोरेट्स की निकट भागीदारी की आवश्यकता है।

जैसे-जैसे हम उबरते हैं, हमें संकट की विरासत से निपटना चाहिए और मजबूत, समावेशी और सतत विकास के लिए स्थितियां बनानी चाहिए। संकट ने जो नुकसान पहुँचाया है उसे सीमित करना केवल पहला कदम था; हमारा प्रयास महामारी के बाद के भविष्य में टिकाऊ और सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए। निजी खपत के स्थायित्व को बहाल करना, जो

ऐतिहासिक रूप से समग्र मांग का मुख्य आधार रहा है, यह आगे चलकर महत्वपूर्ण होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सतत विकास को मध्यम अवधि के निवेश, मजबूत वित्तीय प्रणाली और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से व्यापक आधार पर निर्माण करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, नवाचार, भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर अधिक जोर देने की आवश्यकता होगी। हमें प्रतिस्पर्धा और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने और महामारी प्रेरित अवसरों से लाभ उठाने के लिए श्रम और उत्पाद बाजारों में और सुधार जारी रखना चाहिए। कुछ क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह आवश्यक है कि इस योजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र और कंपनियां इस अवसर का उपयोग अपनी दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में और सुधार करने के लिए करें। दूसरे शब्दों में, योजना से लाभ टिकाऊ होना चाहिए न कि एकमुश्त।

फिर से, वृद्धि के टिकाऊ होने के लिए, हरित भविष्य की ओर संक्रमण महत्वपूर्ण रहेगा। स्वच्छ और कुशल ऊर्जा प्रणालियों, आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरणीय स्थिरता की आवश्यकता पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। जलवायु प्रतिरोधात्मकता की नीतियों को अपनाते समय देश-विशिष्ट विशेषताओं और उनके विकास के चरण को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग देश के दिशानिर्देश पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, जबकि महामारी ने बहुत बड़ी चुनौतियाँ पैदा की हैं, यह विकास के मार्ग को बदलने के लिए एक विभक्ति बिंदु के रूप में भी कार्य कर सकती है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से उत्पादकता, विकास और आय को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी योजनाओं को लागू करने, बेरोजगारों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, महिलाओं के अनुकूल काम के माहौल को बढ़ावा देने और गरीब और हाशिए के वर्गों की शिक्षा का समर्थन करने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा क्योंकि हम कोविड-19 के बाद की अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। डिजिटलीकरण और नवाचार के साथ आय और रोजगार सृजन काफी लोगों के लिए समृद्धि का एक नया युग ला सकता है।

हम में से कई लोग महात्मा गांधी के जंतर[5] को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हुए बड़े हुए हैं - "मैं तुम्हें एक जंतर दूंगा जब भी तुम संदेह में हो... सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करें जिसे आपने देखा हो और अपने आप से पूछें कि क्या आप जिस कदम पर विचार कर रहे हैं वह उसके किसी काम का होगा। क्या इससे उसे कुछ हासिल होगा? क्या यह उसे अपने जीवन और भाग्य पर नियंत्रण करने के लिए बहाल करेगा?" जब हम एक मजबूत और प्रतिरोधी भारत के निर्माण का प्रयास करते हैं, तो ज्ञान का यह मोती जो हमने बहुत पहले सीखा था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

धन्यवाद। सुरक्षित रहें। नमस्कार!

[5] प्यारेलाल, गांधी, एम. (1958)। अंतिम चरण खंड II. अहमदाबाद: नवजीबन पब्लिशिंग हाउस, पी. 65